VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)/GENERAL STUDIES (Paper-III) (2219)

निर्धारित समय: **तीन घंटे**
Time Allowed: ***Three Hours***

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 0089080

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : गौरव कुमार त्रिपाठी

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English
हिन्दी

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)
GENERAL STUDIES (Paper III)

तारीख
Date
28/अगस्त/2022

केंद्र
Centre Academy of Computer Batehata, gorakhpur

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

VISIONIAS

	महत्वपूर्ण अनुदेश उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	**Important Instructions** **Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)	

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ **Marks Details (To be filled by the Examiner(s))**

प्रश्न सं. **Q. No.**	अंक **Marks**		प्रश्न सं. **Q. No.**	अंक **Marks**	
1			**11**		
2			**12**		
3			**13**		
4			**14**		
5			**15**		
6			**16**		
7			**17**		
8			**18**		
9			**19**		
10			**20**		
उप-योग (A) **Subtotal (A)**			**उप-योग (B)** **Subtotal (B)**		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-III)/GENERAL STUDIES (Paper-III) (2219)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे
Time Allowed: **Three** Hours

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. राजकोषीय नीति आय असमानता को कम करने के साथ-साथ सबसे निर्धन और अभावग्रस्त लोगों को देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Fiscal policy can be a key tool to reduce income inequality as well as make the poorest and the downtrodden a part of the country's growth story. Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

राजकोषीय नीति सरकार के आय एवं व्यय पक्ष से संबंधित नीति होती है।
(2022 में भारत का कुल राजकोषीय घाटा - 6.7% रहा है।)

आय असमानता को कम करने में योगदान :

① कर संबंधी नीति → अप्रत्यक्ष कर गरीबों पर अधिक प्रभाव (GDP का 5.7%)
↓
प्रत्यक्ष कर आयानुसार (भारत के GDP का 6.1%)

OECD देशों में यह GDP का 33.5%
अतः अप्रत्यक्ष करों में कमी एवं प्रत्यक्ष कर आधार में वृद्धि आवश्यक

② सब्सिडी नीति — उदा० कृषि जैसे पिछड़े क्षेत्रों में GDP का 2.5-3% सब्सिडी
→ सरकार द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मूलभूत आवश्यकताओं पर व्यय

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

② निर्धन एवं अभावग्रस्तों को विकास धारा में शामिल / समावेशी विकास :

① फूड एवं फर्टिलाइजर सब्सिडी : उदा० PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को सहायता

② रोजगार सृजन : मनरेगा के माध्यम से गरीबी न्यूनीकरण (विश्व बैंक)

③ वंचित वर्गों का कल्याण - छात्रवृत्ति, अवसंरचना विकास आदि पर जोर देकर समावेशी विकास।

हालांकि एक प्रगतिशील राजकोषीय नीति पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय में संतुलन रखती है। भारत सरकार को भी इस संदर्भ में राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

2. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना भूमि सुधार सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय न्यायपालिका पर बोझ को कम करने में भी काफी सहायक होगा। विस्तारपूर्वक समझाइए। साथ ही, इस संदर्भ में किए गए उपायों का भी उल्लेख कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Digitizing land records will go a long way in ensuring land reforms as well as lessening the burden on the Indian Judiciary. Elaborate. Also, state the measures taken in this context. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भूमि सुधार से तात्पर्य जोतदारों एवं भूमि के संबंधों में सुधार है।

अभिलेखों का डिजिटलीकरण एवं भूमि सुधार।

① जमींदारी सुधार : डिजिटलीकरण बेनामी संपत्ती पर रोक लगायेगा तथा जमींदारी कानून उचित प्रकार लागू।

② काश्तकारी सुधार- मालिकाना हक तय होगा तथा मौखिक किरायेदारी व्यवस्था लिखित की ओर बढ़ेगी → पारदर्शिता वृद्धि

③ कांट्रैक्ट फार्मिंग / सहकारी कृषि एवं चकबंदी तथा भू अधिग्रहण को आसान बनायेगी।

न्यायपालिका पर बोझ कमी :

(1) भू संपत्ति विवाद से संबंधित केस अत्याधिक है। - इनका समयबद्ध निपटारा संभव।

(2) भू अधिग्रहण आदि के प्रति

PIL याचिकाओं का बहुआलेख निपटारा संभव।

→ डिजिटलीकरण मध्यस्थ प्रक्रियाओं को बढ़ाकर सहमति से विवाद निपटान हेतु महत्वपूर्ण (e- लोक अदालत आदि से)

सरकार के प्रयास :

(1) राष्ट्रीय भू अभिलेख डिजिटलीकरण कार्यक्रम

(2) स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से मैपिंग एवं अनन्य / अद्वितीय लैंड आई० डी० कार्ड सृजन।

(3) राज्य स्तर पर :- लोकवाणी, रावइट आदि कार्यक्रम।

इसके अलावा भू सुधार हेतु पंचायतों एवं स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण एवं समयबद्ध योजना क्रियान्वयन अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. ऐसा भी कहा जाता है कि अधिकांशतः नॉन-मेरिट सब्सिडी के लिए निधि (फंड) उपलब्ध कराने वाली प्रतिस्पर्धी राजनीति, भारत में कुछ राज्यों को गंभीर राजकोषीय संकट के कगार पर धकेल रही है। इस संदर्भ में, भारत में सब्सिडी व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
It has been pointed out that competitive politics to fund mostly non-merit subsidies is pushing a few states in India to the brink of a deep fiscal crisis. In this context, discuss the need to rationalise the subsidy regime in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एवं विश्व बैंक द्वारा भी बढ़ती नॉन मेरिट सब्सिडी पर चिंता व्यक्त की गयी है।

इससे उत्पन्न राजकोषीय संकट

① तेलंगाना के स्वयं कर राजस्व का 63% मुफ्त उपहारों में

② पंजाब की GDP का 53% ऋण

③ महाराष्ट्र, UP, बिहार सर्वाधिक ऋण ग्रस्त राज्य

नॉन मेरिट सब्सिडीयाँ
- कृषि ऋण माफी
- डिस्कॉम्स पर ऋण लेकिन मुफ्त बिजली एवं पानी आदि।

सब्सिडी व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता।

① समावेशी विकास केन्द्रित हो : सतत विकास लक्ष्यों तथा गरीबी, कुपोषण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवन की प्राथमिकता आवश्यक।

② करदाताओं में विश्वास वृद्धि हेतु।

(2) पूँजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय में संतुलन हेतु।

(3) दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु : हालिया श्रीलंका संकट से तनाव स्पष्ट हुआ है

(4) अन्तरापीढ़ी एवं अन्तर्पीढ़ी न्याय सुनिश्चित करने हेतु।

उपाय : सुब्रह्मण्यम बालाजी वाद में SC के निर्णयानुसार चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन।

(2) DPSPs आधारित क्षेत्रों पर सब्सिडी का प्राथमिकीकरण - गरीबी उन्मूलन।

(3) सब्सिडी व्यवस्था की आउटकम बजटिंग एवं शून्य बजटिंग आदि।

इस प्रकार उचित सब्सिडी व्यवस्था आर्थिक स्थिरता एवं समावेशी विकास दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेगी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

4. सूक्ष्म-सिंचाई में कृषि को एक लाभदायक और टिकाऊ उद्यम में परिवर्तित करने की वृहद् क्षमता है। दिए गए कथन की प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Micro-irrigation has tremendous potential in transforming farming into a profitable and sustainable venture. Discuss the given statement in the context of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सूक्ष्म सिंचाई से तात्पर्य ड्रिप, स्प्रिंकलर आदि के माध्यम से आवश्यकता -नुरूप जल पौधों तक पहुँचाना है।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य - हर खेत को पानी एवं 'हर बूंद अधिक उत्पादन' सुनिश्चित करना है।

कृषि को लाभदायक बनाने हेतु महत्व :
- जल दक्षता एवं उत्पादकता में वृद्धि : वर्तमान में पारंपरिक सिंचाई 30-35% वहीं जबकि सूक्ष्म सिंचाई 60-70% तक
- (2) लागत कम — बिजली एवं जल की बचत।
  - (2) उर्वरकों एवं कीटनाशकों का दक्षतम प्रयोग संभव)

टिकाऊ उद्यम :- मृदा संरक्षण तथा अपरदन में कमी (29.6% -भू भाग निम्नीकरण की समस्या से ग्रस्त

(2) फसल विविधीकरण संभव : बागवानी

आदि इससे आय में वृद्धि तथा कृषक तनाव कम होगा।

③ उर्वरक एवं कीटनाशक 'ट्रेडमिल' (हर बार अधिक की आवश्यकता) से बचाव।

चुनौतियाँ - प्रारंभिक लागत अधिक
→ तकनीकी प्रसार एवं प्रशिक्षण नहीं
(3) सब्सिडी नीति - जल एवं विद्युत पारंपरिक सिंचाई को बढ़ावा देते हैं।
(4) क्षमता 27.5 M हेक्टेयर का 15% ही सूक्ष्म कृषि में शामिल।

सरकार द्वारा इस संदर्भ में सूक्ष्म सिंचाई कोष (5000 करोड़) तथा किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करके सूक्ष्म कृषि का विस्तार किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

5. भारत के विशाल संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता को देखते हुए, यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में प्रशांत महासागर के लघु विकासशील द्वीपीय देशों (PSIDS) की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Given its vast resources and technical expertise, India can play a key role in assisting the Pacific Small Island Developing States (PSIDS) in dealing with the impact of climate change. Analyse. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

प्रशांतमहासागरीय द्वीपीय देश यथा तुवालु, मार्शल द्वीप एवं आसियान आदि जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित हैं।

इनके द्वारा सामना की जा रही चुनौतियाँ	भारत द्वारा अपने संसाधनों के प्रयोग की संभावना
① चक्रवात, तूफान, आदि आपदाओं की बढ़ती संख्या	① Iflow मुंबई एवं RIMES की तर्ज पर पूर्वानुमान तकनीक उपलब्ध करवाना।
② निम्न आय तथा निम्न गुणवत्ता की अवसंरचना	② आपदा प्रत्यास्थ सतत अवसंरचना में सहायता (भुज (भूकंप) के बाद पुनर्निर्माण)
③ ऊर्जा सुरक्षा नहीं तथा आयात पर निर्भरता आर्थिक	③ सौर ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा का दोहन (उदा० लक्षद्वीप में) तथा ब्लू इकोनामी दोहन में सहायता (उदा०-डीप ओशन मिशन

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(4) जल स्तर वृद्धि से कटाव एवं आपदा	(4) जैवविविधता एवं प्राकृतिक संरक्षण संरचना का निर्माण
(5) जलवायु परिवर्तन से प्रभावित तथा क्षति भुगतान नहीं	(6) भारत UN तथा पेरिस समझौते जैसे मंचों पर बेहतरीन नेतृत्व दे सकता है

चूंकि इन देशों का एक तरफ कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तन में न्यून भागीदारी है, वहीं सर्वाधिक प्रभावित यही देश है। अतः भारत द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिजाइलेंट आइलैंड इनीशिएटिव (IRIS) सकारात्मक पहल है।

6. हालिया "पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना (DMP-MoPR)" का उद्देश्य जमीनी स्तर पर आपदा प्रत्यास्थता विकसित करना है। इस संदर्भ में, इस योजना के निर्माण के लिए उत्तरदायी तर्क की विवेचना कीजिए और इसके प्रमुख घटकों पर प्रकाश डालिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The recent "Disaster Management Plan of Ministry of Panchayati Raj (DMP–MoPR)" aims to develop disaster resilience at the grassroots level. In this context, discuss the rationale behind the formulation of the Plan and highlight its key components. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत का 40% से अधिक भूभाग किसी न किसी आपदा के प्रति सुभेद्य है ऐसे में प्राथमिक उत्तर प्रदाता के रूप में पंचायती राज संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उत्तरदायी तर्क : (1) आपदा पूर्व चरण

(1) स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं के बारे में बेहतर जानकारी
(2) सुभेद्य समूहों की पहचान
(3) पूर्वानुमान सूचनाओं को स्थानीय भाषाओं में पहुँचाना
(4) प्राथमिक उत्तर प्रदाता - अतः प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आवश्यक

(2) आपदा दौरान चरण - शरण स्थलों का प्रयोग
→ खाद्य एवं स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध करवाने में सक्षम
→ (3) लापता वर्गों की जानकारी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

आपदा पश्चात — विल्ड, बैक, बेटर एवं पुर्नवास सहायता का पारदर्शिता पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर सकते है।

पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना के घटक।

1. पंचायतों का सामूहिक प्रशिक्षण एवं तैयारी आंकलन।
2. पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं पारंपरिक ज्ञान का प्रयोग तथा समन्वय
3. सुभेद्य वर्गों की रक्षा एवं क्षमता निर्माण पर जोर।
4. पंचायतों को तकनीकी एवं मानव संसाधन से सक्षम बनाना
5. आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना एवं शरण स्थली का निर्माण।

7. राज्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उभरती एवं विघटनकारी प्रौद्योगिकियों (EDT) के उपयोग से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा संबंधी निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the internal security implications emanating from the use of Emerging And Disruptive Technologies (EDT) by state and non-state actors. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में उभरती एवं विघटनकारी तकनीकों के प्रयोग ने नयी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को उत्पन्न किया है।

आंतरिक सुरक्षा निहितार्थ

तकनीकें	चुनौतियाँ
(1) माइक्रोवेव रेडिएशन का प्रयोग। (चीन, USA, रूस आदि)	सीमावर्ती सुरक्षा परिदृश्य जटिल तथा अदृश्य बनेगा।
(2) क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से धन अंतरण एवं कूटनीतिक / कूट संदेश	(2) विजेतोंसे काटेल होगा तथा संगठित अपराध (तस्करी, मादक द्रव्य, हथियार आदि वृद्धि)
(3) हैंड हेल्ड तथा पोर्टेबल डिवाइसें, आतंकियों द्वारा सैटेलाइट का प्रयोग	→ (3) मुंबई हमले जैसी चुनौतियाँ उत्पन्न
(4) क्वांटम तकनीक तथा जैविक हमले	कोविड-जैसी महामारी तथा आंतरिक परिसंपत्तियों पर खतरे

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

आगे की राह : (1) अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग।

(2) इन तकनीकों के प्रयोग तथा सुरक्षा आदि में विवेक

(3) ड्रोन एवं सैटेलाइट ट्रैकिंग का विकास करना।

(4) FATF आदि के द्वारा उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

इस संदर्भ में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता देखते हुए विदेश मंत्रालय के अंतर्गत NEST प्रभाग सराहनीय कदम है।

8. अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने में भारत द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं की पहचान कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Identify the impediments faced by India in boosting its defence exports. Also, discuss the steps taken by the government in this regard. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2016-17 के 1521 करोड़ से 2021-22 में रक्षा निर्यात 7000 करोड़ पहुँच गया है।

हालांकि अभी भी प्रमुख रक्षा निर्यातकों में 35वीं स्थान निम्न बाधायें दर्शाता है

1. प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण : नवीन तकनीकें नहीं तथा असेंबली एवं सोर्सिंग ही आधीन।
2. नवीन उत्पाद तथा R&D पर जोर नहीं भारत से निर्यातित अधिकांश उत्पादों में पेटेंट स्वामी कंपनियों के पास जिससे अधिकांश लाभ उन्हें प्राप्त
3. समझौतों में देरी तथा समय बद्ध आपूर्ति का अभाव : मुख्यतः आर्डिनेंस फैक्ट्री पर निर्भरता अधीन
4. आत्मनिर्भरता - कच्चे माल तथा रणनीतिक खनिजों एवं सेमीकंडक्टर

आदि हेतु चीन तथा अन्य देशों पर निर्भर

(5) कूटनीतिक - उदा० - अर्जेन्टीना से तेजस समझौते में पाश्चात्य देश बाधक

सरकार के कदम :

(1) रक्षा क्षेत्र में 74% FDI की अनुमति।

(2) स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने हेतु SRIJAN पोर्टल।

(3) रक्षा स्वदेशीकरण → नवीन खरीद नीति
→ CDS का गठन
→ 100 से अधिक उत्पादों के आयात पर रोक

(4) कूटनीतिक समझौते → भारत वियतनाम-एवं फिलीपींस
→ ब्रह्मोस, तेजस आदि हेतु मलेशिया, फिलीपींस जैसे बाजारों की पहचान।

इसके अलावा भारत को रक्षा आधुनिकरण एवं नौकरशाही गतिशीलता के द्वारा रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया। फार इंडिया एंड वर्ल्ड' की स्थापना करनी होगी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

9. अंतरिक्ष मलबे से जुड़े विविध मुद्दों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस खतरे से निपटने के लिए हाल के दिनों में की गई पहलों का भी उल्लेख कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the multiple issues associated with space debris. Also, state the initiatives taken in recent times to tackle this menace. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में स्पेसएक्स द्वारा 16000 से अधिक सैटेलाइटों को निम्न भू कक्षा में (स्टार लिंक) की स्थापना अंतरिक्ष मलबे के मुद्दे को पुनः चर्चा में लाई है।

मलबा – प्राकृतिक अथवा कृत्रिम वस्तु जो अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के ऊपर खतरा है।

मुद्दे
① केसलर सिंड्रोम : एक मलबा अन्य से टकराकर चुनौती पैदा करने में सक्षम।
② चीन आदि देशों की पारदर्शिता में कमी → हाल ही में तियांगगोंग स्टेशन हेतु प्रेषित रॉकेट मलेशिया में गिरा।
③ मलबों की ट्रैकिंग कठिन : अचानक से कई मलबे आ जाते हैं।
④ अंतरिक्ष परिसंपत्तियों पर खतरे :

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उदा० भारतीय उपग्रहों आदि पर

(5) विकासशील देश : जो भविष्य में उपग्रह प्रक्षेपित करेंगे, उनके लिए स्थान की कमी।

(6) इस संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों की कमी।

पहल - (1) रिमूव डेब्रीज मिशन - EU के द्वारा।

(2) बाह्य अंतरिक्ष समझौते तथा हथियारों आदि की स्थापना पर रोक

(3) नासा. एवं जाक्सा द्वारा नेटिंग के माध्यम से मलबे वापस लाने का प्रयास।

(4) पुर्नप्रयोज्य वाहनों का विकास (उदा० इसरो ने हाल ही मे अपने PSLV के अंतिम चरण को ही उपग्रह के रूप में प्रयोग किया।

10. भारत में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) को अपनाने से उपभोक्ताओं के लिए ई-कॉमर्स के अधिक समावेशी और सुलभ बनने की संभावना है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
The adoption of Open Network for Digital Commerce (ONDC) in India is expected to make e-commerce more inclusive and accessible for consumers. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में भारत सरकार द्वारा खुले एवं डिजिटल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में ONDC को अपनाया गया।

वर्तमान ई-कॉमर्स

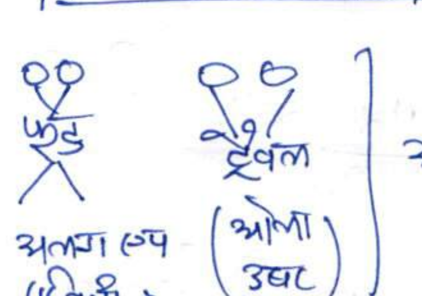

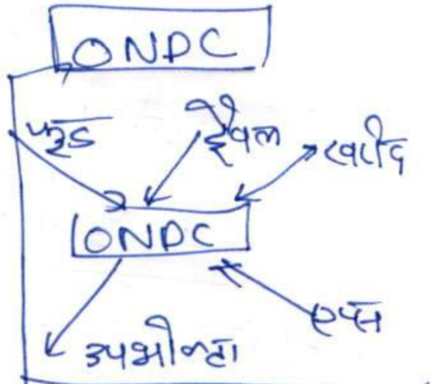

लाभ (1) उपभोक्ताओं को — एक प्लेटफार्म पर सभी उत्पाद एवं मूल्यों में कंपैरिजन संभव।

(2) एकाधिकारवादी प्रवृत्ति से रक्षा : उदा. अमेजन फ्लिपकार्ट कुछ विशेष कंपनियों के उत्पादों को वरीयता प्रदान करते हैं।

(3) बेस्ट डील का चयन आसान : सारे उत्पाद सामने।

(4) नये स्टार्ट अप्स एवं उपभोक्ता

इससे जुड़ेगा।
(5) इसका प्रयोग कहीं भी और कभी भी संभव।

चुनौतियाँ - (1) प्रौद्योगिकी एवं व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप व्यापार सुगमता को क्षति पहुँचा सकता है?
(2) निरंतर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ को संभालना चुनौतिपूर्ण है। (वर्तमान में रिटेल का 10-15% ई-कामर्स है)
(3) अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि कंपनियों को साथ लेकर चलना → रोजगार सृजन एवं संवृद्धि हेतु महत्वपूर्ण।

हाल ही में माइक्रोसाफ्ट की ONDC में भागीदारी की घोषणा निश्चय ही इसे UPI के समान सफल बनायेगी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

11. यद्यपि, हाल ही में "क्षतिकारक" सरकारी मत्स्यन सब्सिडी को रोकने के लिए डब्ल्यू. टी. ओ. के मंच पर एक समझौते पर सहमति बनी है, तथापि, भारत द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं से पता चलता है कि इस मामले में और अधिक वार्ता किए जाने की आवश्यकता होगी। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
While an agreement was recently reached at the WTO on a deal to curb "harmful" government fisheries subsidies, certain concerns raised by India suggests that the matter will require further negotiations. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में मत्स्यन सब्सिडी रोकने हेतु WTO की विशेष बैठक में स्वीकृति बनी है।

समझौते के उद्देश्य -

1. हानिकारक एवं पर्यावरणीय क्षति पहुंचाने वाली मत्स्यन प्रक्रियाओं पर रोक।
2. वाणिज्यिकृत मत्स्यन हेतु सब्सिडी में कमी।
3. समुद्री जैव विविधता का संरक्षण एवं संवर्धन।

| भारत द्वारा उठाई गयी चिंतायें |

1. खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका सुरक्षा - मुख्य तौर पर भारत के तटीय क्षेत्र के लगभग 9 करोड़ मछुआरों की आय का प्रमुख स्रोत।

(2) असमान सब्सिडी : चीन 2.3 B$, जापान तथा USA >2 B$ जबकि भारत केवल 227 M$ ही सब्सिडी पर व्यय।

(3) इस समझौते में कॉमन बट डिफरेंसिएटेड रिस्पांसिबिलिटी पर जोर देना चाहिए
- विकसित देशों में मत्स्य उद्योग पहले से सुदृढ़ है।
- विकसित देशों को 2027 तक सब्सिडी पर पूर्ण रोक जबकि विकासशील एवं गरीब देशों को लंबी संक्रमणकालीन अवधि प्रदान की जानी चाहिए।

(4) अवैध मत्स्यन पर रोक - असंधारणीय प्रथाओं द्वारा दूसरे देशों के विशेष आर्थिक जोन में मत्स्यन पर रोक लगानी चाहिए।

(5) समानता हेतु विकासशील देशों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

WTO में कृषि पर समझौते का अत्यधिक समय बीत जाने पश्चात भी क्रियान्वयन न होना, ~~~~ मत्स्यन सब्सिडी की कमी हेतु सहमत देशो में पुनर्वार्ता एवं नेगोशिएशन को सुनिश्चित कर सकता है। अतः ऐसे मौके का लाभ उठाकर खाद्य एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दो के समाधान के प्रयास किए जाने चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

12. सड़क निर्माण क्षेत्रक में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) से जुड़े लाभों के बावजूद, विभिन्न कारणों से इसमें रुचि कम हुई है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Despite the advantages that are associated with the hybrid annuity model (HAM) in the road construction sector, the interest in it has moderated due to various reasons. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सरकारी एवं निजी भागीदारी हेतु प्रचलित विभिन्न मॉडलों में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल अत्यंत लाभकारी है।

HAM = [बिल्ड आपरेट टोल] BOT तथा EPC (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) इन दोनों का हाइब्रिड है।

लाभ —
① जोखिम - भूमि अधिग्रहण आदि सरकार की जिम्मेदारी।
② वित्तीय पूर्णता - सरकार लागत का 40% प्रारंभ में जबकि 60% वार्षिक किश्तों में भुगतान करती है।
③ निजी सेक्टर की तकनीकी एवं कार्यात्मक दक्षता का लाभ प्राप्त
④ कार्यों में देरी नहीं।

2025-26 तक अवसंरचना में 1.4 T$

से अधिक निवेश की आवश्यकता के बावजूद HAM मॉडलों में रुचि कम हुयी है।

(1) लागत अस्थिरता : स्टील, सीमेंट एवं मजदूरी आदि कीमतों में गुणोत्तर वृद्धि, जबकि समझौतों पर इसका ध्यान नहीं।

(2) जोखिम निर्धारण एवं पूर्वानुमान में लचीलेपन की कमी → अधिकांश परियोजनाएँ पुर्नसमझौते के अभाव में लंबित।

(3) L1 मॉडल का चयन : कन्सल्टेंसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार L1 मॉडल (न्यून लागत मॉडल) ग्रहणता, विलंबता एवं खराब गुणवत्ता वाले कार्यों तथा मध्यस्थता को बढ़ावा देता है। (NHAI की परियोजनाओं में)

(4) वित्तीय बाधायें : बैंकों का बढ़ता NPA अतः ऋण देने के उत्सुक नहीं
→ निर्माण कंपनियों का दिवालियापन।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(5) प्रतिस्पर्धी मॉडल : स्विस चैलेंज आदि का आगमन।

(6) नौकरशाही बाधाएँ - तकनीकी आदि मानदंडों पर स्वीकार करना
→ भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार आदि

सरकार के प्रयास — राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन के तहत 2025 तक 6 लाख करोड़ की प्राप्ति।
- पारदर्शिता एवं दक्षता हेतु 'गति शक्ति' परियोजना।

इसके अलावा केलकर समिति की सिफारिशों के अनुरूप जोखिम निर्धारण तथा समझौतों का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए।

13. मौजूदा एम. एस. पी. खरीद व्यवस्था न तो आर्थिक दृष्टि से और न ही कृषि-पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय है। सविस्तार वर्णन कीजिए। साथ ही, मौजूदा एम. एस. पी. व्यवस्था में सुधार के लिए अपनाए जा सकने वाले वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The existing MSP procurement regime is neither economically nor agro-ecologically sustainable. Elaborate. Also, evaluate the alternative approaches that can be adopted to improve the existing MSP regime. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए। Candidates must not write on this margin

एम॰ एस॰ पी॰ व्यवस्था फसलों मौसम में अधिक उत्पादन के बावजूद किसानों की आय स्तर सुनिश्चित करने हेतु (लागत का 1.5 गुना) सरकार द्वारा खरीद व्यवस्था है।

कमियाँ

① आर्थिक दृष्टि से — किसानों हेतु
→ फसल की उचित कीमत न मिल पाना
केवल 6% किसानों को ही लाभ

② उपभोक्ता हेतु — अधिक आपूर्ति के बावजूद कीमतें अधिक
→ बिचौलियों द्वारा कीमत वृद्धि

③ सरकार हेतु — भंडारण, खरीद तथा परिवहन पर अत्यधिक व्यय

④ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु — उचित कीमतों पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं
→ APMC मंडियों से खरीद की बाध्यता
→ भंडारण नहीं कर सकते।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कृषि पारिस्थितिक दृष्टि से असंधारणीयता

- एकल फसली कृषि – गेहूँ - चावल आदि
- उर्वरक एवं कीटनाशकों का दुरुपयोग → NPK की 4:2:1 के अनुपात के बजाय 8:3:1 है।
- जल गहन फसलें : गन्ना, चावल आदि कृषि क्षेत्र में जल उपयोग कुल उपयोग का > 80% है।
- भूमि उत्पादकता की हानि : तथा NO_x उत्सर्जन, पराली दहन आदि

वैकल्पिक तरीके : मूल्यांकन

① **मूल्यांतर भुगतान**

लाभ – सरकार को खरीद की बाध्यता नहीं।
- किसानों की आय सुनिश्चित।
- बाजार हस्तक्षेप न्यूनतम

हानि – खाद्य सुरक्षा हेतु अन्न की कमी।
- लाभ अंतरण सुनिश्चित करना कठिन
- बाजार प्रणाली अदक्ष है।

② निजी स्टॉकिस्ट खरीद : सरकार द्वारा निजी सेवक को MSP पर खरीद

सुनिश्चित करने उन्हें भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण आदि में सहायता करना।

लाभ - बाजार दक्षता वृद्धि
→ निजी निवेश → उच्च आय सुनिश्चित
→ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित

चुनौतियाँ - मूल्य निर्धारण हस्तक्षेप
→ निजी क्षेत्र की सीमित क्षमता

आगे की राह : साक्षियों युक्तिकरण
→ फसल विविधीकरण - मोटे अनाजों, दालों में वृद्धि
→ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - PM किसान योजना
→ फसल उत्पादकता एवं तकनीकी प्रसार हेतु सहायता (तेलंगाना की रायथु बंधु योजना)

इसके अलावा ZBNF, रसायनमुक्त, हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकें एवं कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए।
Candidates must not write on this margin

14. यह तर्क दिया जा रहा है कि भारत गोदामों में खाद्यान्नों की अधिकता से जूझ रहा है। भारत की मौजूदा बफर स्टॉक नीति को ध्यान में रखते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
It is being argued that India is struggling with overflowing foodgrains in warehouses. Discuss the statement in view of the existing buffer stock policy of India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत सरकार की मौजूदा बफर स्टॉक नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के तहत 70 करोड़ से अधिक भारतीयों को खाद्य सुरक्षा एवं खाद्यान्न मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है।

भारत गोदामों में खाद्यान्न की अधिकता से जूझ रहा है।
- → गेहूँ का स्टॉक - आवश्यकता से 3गुना
- → चावल का स्टॉक - आवश्यकता से 2गुना
- → CAG की रिपोर्ट के अनुसार रखरखाव के अभाव में 35000 करोड़ के खाद्यान्न खुले में सड़ गये
- → भंडारण क्षमता <60MT जबकि भंडारण 200MT से अधिक

इतने भंडारण के पक्ष में तर्क:
(1) खाद्य सुरक्षा - कोविड-19 के दौरान

८० करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज प्रदान करना संभव हुआ।

② कृषक आय सुनिश्चित होती है।

③ बाजार मूल्य नियंत्रण।

④ फसल विफलता की स्थिति में रक्षा।

विपक्ष में तर्क: ① खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बाधा (कच्चे माल उपलब्ध नहीं)

② WTO आदि मंचों पर आलोचना

③ आवश्यकता से अत्यधिक भंडारण से क्षति ~~एवं~~ अदक्षता तथा लागत वृद्धि

आगे की राह

① नवीन भंडारण तकनीकों का प्रयोग - सोलर ड्रायर आदि।

② प्रसंस्करण उद्योगों को खुली बिक्री तथा निर्यात की अनुमति

③ फसल विविधीकरण - खाद्यान्न के साथ फलों एवं मोटे अनाजों का भंडारण किया जाये।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए।
Candidates must not write on this margin

(4) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आधिक आवंटन
(5) भंडारण अवसंरचना हेतु निजी क्षेत्र सहयोग लिया जाये।

इस प्रकार एक पक्ष भंडारण नीति गरीबी एवं खाद्य सुरक्षा के SDG-1,2 की प्राप्ति तथा खाद्यान्न भंडारण अधिकता के मध्य संतुलन स्थापित करेगी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. हाल ही में, सरकार ने सभी पत्तनों (पोर्ट्स) को वर्ष 2047 तक स्वयं को 'मेगा पोर्ट्स' के रूप में विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निर्देश दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में, पत्तनों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और साथ ही, भारत की ब्लू इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Recently, the government has asked all ports to prepare a master plan in order to become 'mega ports' by 2047. In light of this, discuss the challenges faced by ports and suggest remedial measures in order to propel India's blue economy. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए। Candidates must not write on this margin

भारत के कुल आयात/निर्यात का 70% पत्तनों के माध्यम से होता है। ऐसे में 2047 तक पत्तनों का मेगा पोर्ट्स में विकास निम्न चुनौतियों का समाधान कर सकता है।

चुनौतियाँ

① प्राकृतिक

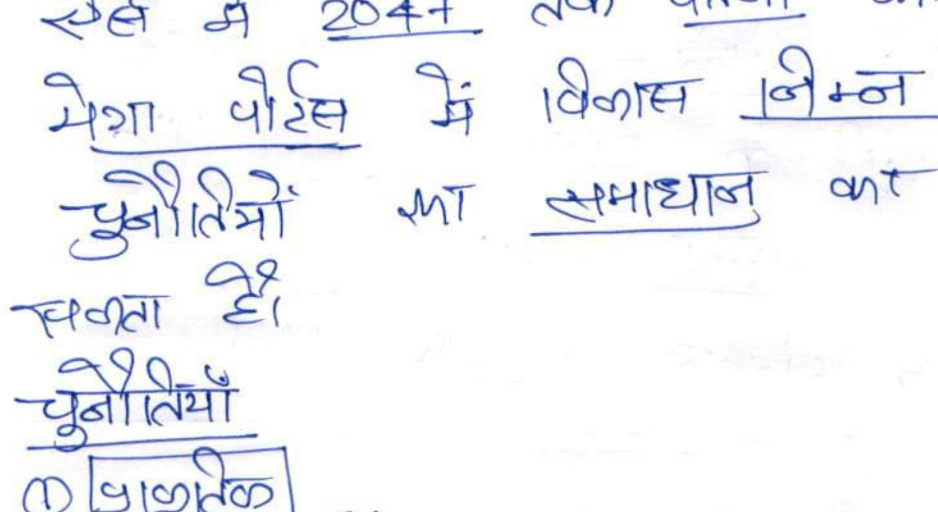

② हिंटरलैंड से कनेक्टिविटी का अभाव

③ बड़े पोत प्रयोग करने की क्षमता नहीं - वर्तमान में सिंगापुर अथवा

श्रीलंका जाना पड़ता है। वहाँ से छोटे पोतों में सामान भारत।

④ औसत टर्नअराउंड समय : भारत > 2 दिन सिंगापुर, चीन < 1 दिन

⑤ तकनीकी क्षमता का अभाव : पोत गहरीकरण आदि

⑥ पोत विनिर्माण न्यून : चीन विश्व का 40%, जबकि भारत < 1% पोत निर्माण

⑦ पत्तन हेतु निर्देशित जहाजों आदि में विदेशी स्वामित्व ⇒ व्यापार सुगमता में बाधा।

⑧ अधिक छोटे पत्तन – केवल 13 बड़े पत्तन, जबकि > 200 लघु पत्तनों में सुरक्षा का अभाव।

ब्लू इकोनामी को आगे बढ़ाने के उपाय।

① पोर्ट आधारित विकास – हिंटरलैंड से कनेक्टिविटी बढ़ाना (सागरमाला कार्यक्रम)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

② पत्तन अवसंरचना निर्माण :- निजी निवेश में वृद्धि
↳ प्रसंस्करण उद्योगों हेतु
प्रशीतलन, भंडारण आदि सुनिश्चित करना

③ सतत् विकास - रो-रो पर्यटन, समुद्री जेट आदि का प्रयोग किया जाये

④ पत्तनों की क्षमता वृद्धि - ① तकनीकी हस्तांतरण (USA, यूरोप से)
↳ पोत निर्माण उद्योग को बढ़ावा
↳ ड्रेजिंग सुविधाओं में वृद्धि

⑤ नौकरशाही बाधायें कम करना

⑥ आपदा प्रत्यास्थता सुनिश्चित करना। तथा अनुसंधान (डीप ओशन मिशन, पाली मेटालिक नोड्यूल का खनन)

~~~~ खनिजों का दोहन

सतत विकास लक्ष्यों तथा 2025 तक 5 T $ अर्थव्यवस्था बनने हेतु महत्वपूर्ण है।
~~~~

16. आय और संपदा में असमानता कार्बन असमानता में परिवर्तित हो जाती है। इस संदर्भ में, भारत के लिए कार्बन असमानता को दूर करने के महत्व पर चर्चा कीजिए और इसे प्राप्त करने के उपायों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Inequality in income and wealth translates into carbon inequality. In this context, discuss the significance of addressing carbon inequality for India and suggest ways to achieve it. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कार्बन असमानता से तात्पर्य समाज के गरीब तथा निम्न वर्गों का कम कार्बन उत्सर्जन जबकि CO_2 प्रेरित जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होना है।

(भारत - केवल 3% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन जबकि 27 M लोग जलवायु प्रेरित विस्थापन से त्रस्त)

कार्बन असमानता को दूर करने का महत्व :

(1) समावेशी विकास - क्योंकि यह सभी वर्गों के मध्य असमानता कम करेगा।

(2) संधारणीय विकास - सुभेद्य वर्गों की जलवायु परिवर्तन से रक्षा सुनिश्चित करते हुए।

(3) नेट शून्य लक्ष्य की प्राप्ति संभव (2070 तक)

④ स्वच्छ ऊर्जा एवं संधारणीय औद्योगीकरण में मददगार।

⑤ प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, आपदाओं आदि के प्रभाव में कमी।

उपाय - ① कृषि संधारणीयता - कुल उत्सर्जन का > 15%. अत: उर्वरकों, कीटनाशकों एवं सिंचाई साधनों के प्रयोग में दक्षता लाना चाहिए (PM कृषि सिंचाई योजना)

② उद्योग संधारणीयता - प्रदूषण में कमी तथा स्वच्छ तकनीकें।
→ ऊर्जा दक्षता में वृद्धि (PAT योजना)

③ कार्बन कर → प्रदूषण अनुपात कर के आधार पर तथा इसका निवेश सुभेद्य वर्गों एवं स्थानीय समुदायों के पुनर्वासीकरण एवं आजीविका सृजन में

④ एक कार्बन बाजार सुनिश्चित करना इससे कार्बन असमानता का व्यापार के माध्यम से समता सुनिश्चित होगी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

⑤ तकनीकी विकास - कार्बन कैप्चर एवं यूटिलाइजेशन
→ अल्ट्रा एवं सुपर अल्ट्रा कोयला संयंत्रों का निर्माण

⑥ आय असमानता में कमी →
→ सुभेद्य वर्गों को पारिस्थितिकीय सेवाओं हेतु भुगतान (पालमपुर मॉडल जहाँ ग्रामीण लोगों को स्वच्छ जल आपूर्ति हेतु भुगतान होता है)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

17. भारत में पिछले एक दशक के दौरान भूस्खलन की बढ़ती और नियमित घटनाओं के बावजूद, विकास के प्रमुख प्रतिमानों (पैरडाइम) में कोई मुख्य संशोधन नहीं किया गया है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Despite increased and regular occurrences of landslides over the past decade in India, the dominant development paradigm has largely not been modified. Examine. (Answer in 250 words)15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भूवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार भारत का 12% से अधिक भू-भाग, जबकि हिमालय का 37% भू-भाग भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है।

→ केदारनाथ हादसा
→ ऋषि गंगा नदी हादसा आदि)

भूस्खलन संभावित क्षेत्र

बढ़ती घटनाओं के बावजूद विकास प्रतिमानों में संशोधन नहीं।

① सुभेद्य क्षेत्रों में निर्माण कार्य गतिशील
- → हिमालय में चार-धाम प्रोजेक्ट
- → कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट।

② क्षेत्रीय विशेषज्ञ लोगों का भागीदारीकरण का अभाव तथा भवन निर्माण संहिताओं का प्रयोग नहीं।

③ विशिष्ट पूर्वानुमान तंत्रों का निर्माण नहीं

④ मानव प्रेरित भूस्खलन कारकों में वृद्धि
→ छोटा नागपुर में अत्यधिक खनन
→ पश्चिमी घाट में रोपण कृषि-चाय
→ उत्तर-पूर्व में झूम कृषि आदि

⑤ जलवायु परिवर्तन प्रेरित सुभेद्यता आंकलन नहीं।

⑥ जोखिम की पहचान एवं निवेश में अभाव।

सरकार के प्रयास : NDMA द्वारा इसरो की सहायता भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र मानचित्रण।
- परियोजनाओं का EIA अनिवार्य
- सेंडाई फ्रेमवर्क तथा प्रधानमंत्री की 10 सूत्री आपदा प्रबंधन रणनीति के अनुरूप स्थानीय समुदायों का क्षमता निर्माण।
→ पर्वतमाला कार्यक्रम → पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क के बजाय रोपवे कनेक्टिविटी

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

आगे की राह :

① संभावित क्षेत्रों में निर्माण पर रोक
② तकनीकी प्रयोग - प्रतिघाती दीवारें एवं जियो टैक्सटाइल का प्रयोग।
③ जापान, एवं ताइवान जैसे प्रभावित देशों से सीखना तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन।
④ स्थानीय समुदायों का क्षमता निर्माण तथा पूर्वानुमान तंत्र का विकास

ध्यान रहे भूस्खलन की क्षति मानव प्रेरित कारकों से बढ़ जाती है, अतः प्राकृतिक पारितंत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप अनिवार्य है।

18. राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ वैध सीमा-पार प्रवाह को संतुलित करने के लिए भारत को एक स्मार्ट सीमा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहलों को रेखांकित कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

India needs a smart border management system to balance legitimate cross border flows with national security interests. Discuss. Also, highlight the initiatives taken by the government in this regard. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

स्मार्ट सीमा प्रबंधन प्रणाली मानव एवं तकनीक का समन्वय होती है। जो एक-दूसरे की कुशलता के आधार पर सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करती है,

आवश्यकता — ① वैध सीमा पार प्रवाह

→ भारत गोल्डेन ट्राइंगल एवं गोल्डेन क्रिसेंट जैसे मादक द्रव्यों एवं हथियार

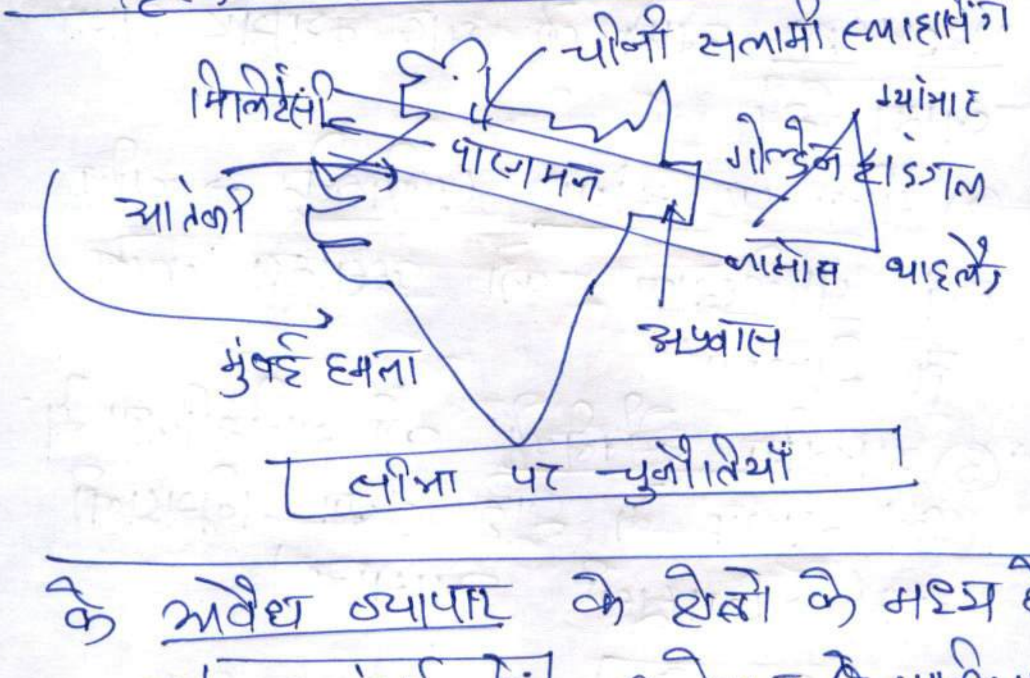

सीमा पर चुनौतियाँ

के अवैध व्यापार के क्षेत्रों के मध्य है.

अतः इस संदर्भ में — ① नेपाल से, पाकिस्तान से जाली नोट

→ मानव एवं ड्रग्स की तस्करी रोकने हेतु आवश्यक।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

② जटिल भूगोल → उदा० चीन के साथ पर्वतीय सीमा, बांग्लादेश के साथ दलदल एवं पाकिस्तान के साथ नदीयाँ → मानव सीमा सुरक्षा की सीमायें हैं।

③ मानव श्रम 24×7 कार्यरत नहीं रह सकता जबकि राज्य प्रेरित अतिक्रमी मौके की तलाश में रहते हैं।

④ राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों का संरक्षण

- ① पूर्वोत्तर में उग्रवाद नियंत्रण - उदा० NSCN(K) हमले के बाद म्यांमार भाग जाता है।
- ② सीमा पर संचार सुनिश्चित → चीन एवं पाकिस्तान को दुस्साहस करने से रोकेगा।
- ③ भारतीय सैनिकों की गतिशीलता में एवं सुरक्षा में वृद्धि तथा निगरानी एवं जासूसी आसान।

सरकार की पहलें

① CIBMS प्रणाली - ये तकनीकी हथियारों (हैंड हेल्ड थर्मल इमेजिंग)

एवं इंटीग्रेटेड सीमा प्रबंधन तथा विशिष्ट आप्टिकल संचार प्रणाली का संयुग्मन है।

② बोल्ड QIT - स्मार्ट बाड़ों से बांग्लादेश की सीमा पर लेजर, कैमरे आदि की तैनाती की गयी है।

③ म्यांमार - पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर प्रायोगिक तौर पर लेजर बाड़बंदी की जा रही है।

हालांकि स्मार्ट बाड़ मनुष्य का विकल्प नहीं हो सकती अतः हैकिंग आदि से सुरक्षात्मक SOP की स्थापना की जानी चाहिए एवं मानव बलों को तीव्र प्रशिक्षण अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

19. वैश्वीकरण और धन शोधन के बीच संबंध स्थापित करते हुए, इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ की गई पहलों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Establishing linkages between globalisation and money laundering, discuss the initiatives taken at the national and international levels to combat it. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

धन शोधन अवैध तरीके (अपराधों) से सृजित आय को अर्थव्यवस्था में वैधतापूर्ण स्थापित करने की प्रक्रिया है,

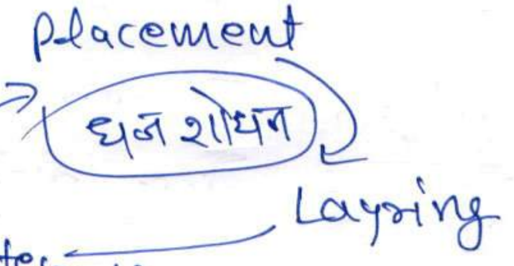

IMF के अनुसार वैश्विक GDP का 2-2.5% धन शोधन से जुड़ा है। जो वैश्वीकरण के कारण वृद्धिशील है।

वैश्वीकरण एवं धनशोधन :

① हवाला प्रक्रियाओं द्वारा धन का स्थानांतरण आसान।

② नयी तकनीकों का आगमन → जैसे क्रिप्टोकरेंसी आदि जिसका विनियमन कठिन है

③ टैक्स हैवन देश तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण शेल कंपनियाँ

तथा आधार क्षरण एवं लाभ अंतरण (BEPS) आसानी से संभव हुआ है।

(7) संगठित अपराध भी वैश्वीकृत हुए हैं। हवाला, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी हथियार आदि की अवैध बिक्री से प्राप्त धन अंतरण अर्थव्यवस्थाओं में सुलभ हुआ है।

(8) NGOs, सोशल मीडिया आदि को प्राप्त अंतरण एवं ई-कामर्स आदि से धन की प्लेसमेंट एवं लेयरिंग आसान हुयी।

(6) कई चरणों के बाद धन के मूल स्रोत का पता लगा पाना कठिन। (उदा० - पाकिस्तान से 1 रुपये का सेब 100 रुपये के भाव पर खरीदना)

राष्ट्रीय पहलें : (1) PMLA एक्ट को मजबूत किया गया तथा धनशोधन को स्वतंत्र अपराध माना गया है।

(2) ED, CBI जैसी विशिष्ट एजेंसियों का निर्माण।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

③ ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को बढ़ावा।

④ संगठित अपराधों हेतु - बेनामी संपत्ति रूट आदि।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर :

① FATF द्वारा ब्लैक लिस्ट एवं ग्रे लिस्ट का प्रयोग

② OECD एवं G-20 देशों द्वारा BEPS पर कार्यवाही तथा हालिया 'ग्लोबल मिनिमम टैक्स' को मंजूरी देना।

③ अमेरिका - इजराइल आदि के साथ द्विपक्षीय सहायता।

इसके अलावा आतंकवाद एवं धन शोधन के संबंधों की स्वीकृति तथा आतंकी वित्तपोषण हेतु सामूहिक कार्यवाही आवश्यक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

20. ऐसे तर्क दिए गए हैं कि भारत को बाह्य अंतरिक्ष की प्रकृति के बारे में अपनी कुछ पुरानी धारणाओं की समीक्षा करने और नए वैश्विक मानदंडों के विकास में योगदान देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, आर्टेमिस समझौते के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

There have been arguments that India needs to review some of its past assumptions about the nature of outer space and contribute to the development of new global norms. In this context, analyse India's stand in relation to the Artemis Accords. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

आर्टेमिस अकॉर्ड पाश्चात्य देशों द्वारा बाह्य अंतरिक्ष के प्रयोग तथा चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के ऊपर भविष्य में मानव मिशन से संबंधित है।

ऐसे में भारत को अंतरिक्ष की पुरानी धारणाओं की समीक्षा करना अनिवार्य है क्योंकि

① अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी
(उदा - चीन एवं USA)

② अंतरिक्ष को हथियारों की स्थापना से मुक्ति हेतु।

③ बाह्य अंतरिक्ष ग्लोबल कॉमन का भाग सुनिश्चित हो सके
↳ चीन तथा रूस चंद्रमा पर बसने की योजना बना रहे हैं।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

नये वैश्विक मानदंडों के विकास में योगदान :

- भारत इस संदर्भ में प्रमुख हित-धारक है।
- (2) विकासशील देशों का पक्ष पोषित व रख सकें
- (3) अंतरिक्ष साझा समृद्धि में योगदान दे।

भारत का दृष्टिकोण :

(1) भारत साझा सहयोग के समर्थन में

(2) बिना भेदभाव सभी की भागीदारी होनी चाहिए।

(3) किसी भी मिशन के गोपनीय उद्देश्य (शस्त्रीकरण) नहीं होना चाहिए।

(4) अंतरिक्ष में गुटबाजी पर रोक लगे।

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में नवीन बाह्य अंतरिक्ष समझौते की स्थापना तथा इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

SPACE FOR ROUGH WORK